

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/295

05/07/2025

को,

Plexconcil के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: इनपुट के संबंध में पेरू और चिली के साथ व्यापार वार्ता

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वाणिज्य विभाग के एफटी (एलएसी) प्रभाग ने भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर चल रही बातचीत तथा पेरू के साथ व्यापार वार्ता के लिए उद्योग से इनपुट का अनुरोध किया है।

भारत और चिली जल्द ही मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते के दायरे को व्यापक बनाने के लिए सीईपीए के लिए दूसरे दौर की वार्ता करेंगे; पहले दौर की वार्ता मई, 2025 में नई दिल्ली में हुई थी।

भारत-पेरू व्यापार समझौते पर बातचीत वर्ष 2017 में शुरू हुई थी और अब तक सात दौर की बातचीत हो चुकी है। सातवां दौर अप्रैल, 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 8वें दौर की बातचीत आने वाले महीने में होने की उम्मीद है।

इस संदर्भ में, वाणिज्य विभाग ने एचएस कोड की सूची मांगी है, जिसके तहत भारत चिली और पेरू से टैरिफ उदारीकरण चाहता है। साथ ही, विभाग ने एचएस कोड के लिए अनुरोध किया है, जिसके तहत भारत चिली और पेरू से आयात पर टैरिफ कम कर सकता है या टैरिफ खत्म कर सकता है।

इस संबंध में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने विचार निम्नलिखित प्रारूप में साझा करें:

चिली के साथ बातचीत के लिए भारत की इच्छा सूची और प्रस्ताव सूची			
एचएस कोड	उत्पाद वर्णन	क्या भारत को अपने निर्यात के लिए चिली से शुल्क में कटौती/शुल्क समाप्ति की मांग करनी चाहिए?	क्या भारत को चिली से आयातित वस्तुओं पर शुल्क कम करना चाहिए/खत्म करना चाहिए?
पेरू के साथ बातचीत के लिए भारत की इच्छा सूची और प्रस्ताव सूची			
एचएस कोड	उत्पाद वर्णन	क्या भारत को अपने निर्यात के लिए पेरू से	क्या भारत को पेरू से आयातित वस्तुओं पर

		शुल्क में कटौती/शुल्क उन्मूलन की मांग करनी चाहिए?	शुल्क कम करना/समाप्त करना चाहिए?
--	--	---	-------------------------------------

आपके सुझावों से सरकार को चिली और पेरू के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर बातचीत करने में मदद मिलेगी और हम 9 जुलाई, 2025 तक आपसे सुनने की आशा करते हैं।

यदि आपको किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो, तो

कृपया bharti@plexconcil.org ; research@plexconcil.org पर संपर्क करें।

सम्मान,

भारती परवे

उप निदेशक — व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद